bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org संवत 2082 युगाब्द 5127 कुल पृष्ठ–32, अप्रैल द्वितीय अंक 2025, वर्ष–36 : अंक–18

वर्तमान

कमल ज्योति

₹20

"एक राष्ट्र, एक चुनाव"

वक्फ सुधार जनजागरण अभियान

संगोष्ठी

स्व. बाबूजी कल्याण सिंह जी की स्मृति में सर्व समाज को समर्पित
नि:शुल्क लाइब्रेरी, कोचिंग एवं करियर काउंसलिंग सेन्टर
लोधी छात्रावास उद्घाटन समारोह

वर्तमान

कमल ज्योति

संरक्षक

श्री भूपेन्द्र सिंह

सम्पादक

अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध/कार्यकारी सम्पादक

राजकुमार

प्रकाशक

प्रो0 श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक

ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग

लखनऊ – 1

फोन :– 0522–2200187

फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

www.up.bjp.org
bjpkamaljyoti
Vartman Kamaljyoti
@bjpkamaljyoti

तुमने दिया देश को जीवन,
देश तुम्हें क्या देगा।
अपनी आग तेज करने को,
नाम तुम्हारा लेगा।।

सम्पादकीय

पहलगाम आतंकवादी हमला, सरकार लेगी बदला

भारत में आतंकवादी गतिविधियों की जिस प्रकार से कमर टूट रही है उसे जीवित करते हुए पाकिस्तान की सेना एवं आतंकवादीयों ने कश्मीर में पुनः हमला किया।

कश्मीर घाटी के पहलगाम हमले में 26 निहत्थे निर्दोष पर्यटकों की धर्म पूछकर और कलमा न पढ़ पाने पर की गई। नृशंस हत्याओं के बाद, देश में आतंकवाद के खिलाफ भीषण आक्रोश है। देश का जन जन पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तड़प रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की मधुबनी रैली में और फिर "मन की बात" रेडियो कार्यक्रम में देश को विश्वास दिलाया है कि पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा तथा पाकिस्तान को ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। आतंकवादी घटनाओं के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि देश के गृहमंत्री तुरंत अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके घटनास्थल पहुंचे और पीड़ितों के साथ खड़े रहे। इस घटना के बाद से भारत के आतंकवाद से निपटने के निर्णय को विश्व के सभी प्रमुख देशों ने अपना पूरा समर्थन दिया है। लगभग पूरा वैश्विक समुदाय संकट की इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद औरआम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बयानबाजी कर रहे हैं इन नेताओं के गिरे हुए स्तर का प्रमाण है। पाकिस्तानी माडिया व यूटूबर्स विरोधी दलों के इन्हीं नेताओं के बयानों को आधार मानकर भारत के खिलाफ प्रोपोगैंडा चला रहा है।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव को राज्य में मुस्लिम तुष्टिकरण और पीडीए राजनीति की चिंता है और यही कारण है कि वे कहते हैं कानपुर के शहीद शुभम् द्विवेदी के परिवार से उनकाकोई संबंध नहीं है और उनके घर जाने का उनके पास समय नहीं हैं ।

पाकिस्तान टीवी पर भारत के विरोधी दलों के नेताओं के बयान चल रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े एक्स अकाउंट इनको कोट रहे हैं ।आज देश कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है कि उनके और पाकिस्तानी मंत्रियों के बयानों में इतनी समानता क्यों हैं? अचानक सिद्धारमैया सहित कांग्रेस व विरोधी दलों के नेता पाकिस्तानी मीडिया के प्रिय बन गये हैं। ये लोग जो अभी सर्वदलीय बैठक में सरकार के साथ होने का मुखौटा लगाये थे इनका मुखौटा देश के जनमानस के समक्ष उतर चुका है।

अपने नेताओं की बयानबाजी से चौतरफा घिरी कांग्रेस पार्टी ने जब तक अपने नेताओं को अनर्गल बयानबाजी से बचने का निर्देश दिया तब तक बहुत देर चुकी थी लेकिन फिर भी उसके नेताओं ने अपनी पार्टी का निर्देश लेने से इंकार किया। अब भी कांग्रेस पार्टी और इनके पेड हैंडल्स के सोशल मीडिया एकाउंटस को देखा जाये तो वो आपत्तिजनक शब्दावली से भरे पड़े हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने और आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने से पूर्व देश के अंदर छिपे हुए गद्दारों का बेनकाब होना अनिवार्य है फिर वह चाहे राजनैतिक दल हों, नेता हों या किसी अनाम गोपनीय संगठन का कोई भी सदस्य या यूटूबर्स आदि।

राज्य और हर कोने में अभी भी हजारों की संख्या में देशविरोधी अराजक तत्व मौजूद हैं जिन पर भी निर्णायक कार्यवाही का यही समय है। क्यांकि आज पाक प्रोपेगन्डा, जिहादी तंत्र के आधार पर आतंकियों को बचाना चाहता है।

भारत ने नीतिगत फैसले लेते हुए जैसे सिंधु नदी जल समझौते को रद्द किया, यहाँ रह रहे पाकिस्तानियों को बाहर करने का निर्णय लिया। पाक में खलबली मची हुई है। भारत की कड़ी चेतावनी के बाद पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है।

पाकिस्तान अमेरिका सहित चीन, टर्की से भारत से नरम रूख अपनाने के प्रयास कर रहा है। लेकिन 2025 का भारत अब सशक्त भारत है जो अपने निर्णय पर अड़ीग रहता है। इसलिए देश का सरकार को समर्थन है। वह अपने संकल्प को दृढ़ता के साथ पूरा करें।

‘ऐतिहासिक मित्रता, प्रगति के लिए साझेदारी’

क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब साम्राज्य के प्रधानमंत्री महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद के निमंत्रण पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 अप्रैल, 2025 को सऊदी अरब साम्राज्य का राजकीय दौरा किया।

यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सऊदी अरब साम्राज्य की तीसरी यात्रा थी। यह एचआरएच प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद, क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब साम्राज्य के प्रधानमंत्री की सितंबर 2023 में जी–20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने और भारत–सऊदी अरब सामरिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की सह–अध्यक्षता करने की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के बाद हो रही है।

महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री ने अल–सलाम पैलेस, जेद्दा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगवानी की। भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत संबंध हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं, जो विश्वास और सद्भावना से भरे हैं।

दोनों पक्षों ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की ठोस नींव रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, कृषि, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित विविध क्षेत्रों को कवर करने वाली रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से और मजबूत हुई है।

दोनों पक्षों ने आपसी हितों के मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान–प्रदान किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री एचआरएच प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद को विश्व एक्सपो 2030 और फीफा विश्व कप 2034 के लिए सऊदी अरब की सफल बोली के लिए बधाई दी।

दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर रचनात्मक चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत–सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (एसपीसी) की दूसरी बैठक की सह–अध्यक्षता भी की। दोनों पक्षों ने सितंबर 2023 में अपनी पिछली बैठक के बाद से रणनीतिक साझेदारी परिषद की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने दो मंत्रिस्तरीय समितियों के काम के परिणामों (अ) राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति और उनकी उप–समितियां और (ब) अर्थव्यवस्था और निवेश समिति और विभिन्न क्षेत्रों में उनके संयुक्त कार्य समूह पर संतोष व्यक्त किया। इस संदर्भ में, परिषद के सह–अध्यक्षों ने रक्षा सहयोग और पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग पर मंत्रिस्तरीय समितियों को जोड़कर रणनीतिक साझेदारी की गहराई को दर्शाते हुए रणनीतिक साझेदारी परिषद के चार मंत्रिस्तरीय समितियों तक विस्तार का स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने विभिन्न मंत्रालयों की बड़ी संख्या में उच्च–स्तरीय यात्राओं की सराहना की, जिससे दोनों पक्षों में विश्वास और आपसी समझ बढ़ी है। बैठक के अंत में, दोनों नेताओं ने भारत–सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय पक्ष ने सऊदी अरब में रहने वाले लगभग 2.7

मिलियन भारतीय नागरिकों के निरंतर कल्याण के लिए सऊदी पक्ष की सराहना की, जो दोनों देशों के बीच मौजूद लोगों के बीच मजबूत संबंधों और अपार सद्भावना को दर्शाता है। भारतीय पक्ष ने 2024 में हज यात्रा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सऊदी अरब को बधाई दी और भारतीय हज और उमराह तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट समन्वय के लिए प्रशंसा भी की।

हाल के वर्षों में भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक संबंधों, व्यापार और निवेश संबंधों के विकास का स्वागत किया। भारतीय पक्ष ने विज़न 2030 के तहत लक्ष्यों पर हासिल की गई प्रगति के लिए सऊदी पक्ष को बधाई दी। सऊदी पक्ष ने भारत की निरंतर आर्थिक वृद्धि और 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की सराहना की। दोनों पक्ष अपने–अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने और साझा समृद्धि हासिल करने के लिए आपसी हितों के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमत हुए।

दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 2024 में गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स (एचएलटीएफ) के तहत चर्चाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, फिनटेक, डिजिटल बुनियादी ढांचे, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, विनिर्माण और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में भारत में निवेश करने के सऊदी अरब के प्रयास पर, यह नोट किया गया कि उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने कई क्षेत्रों में समझ बनाई है जो इस तरह के निवेश प्रवाह को तेजी से बढ़ावा देगी। उन्होंने दो रिफाइनरियों की स्थापना पर सहयोग करने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स में हुए समझौते का उल्लेख किया। कराधान जैसे क्षेत्रों में इस टास्क फोर्स द्वारा की गई प्रगति भी भविष्य में अधिक सहयोग के लिए एक बड़ी सफलता थी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने की अपनी इच्छा की पुष्टि की। भारतीय पक्ष ने पीआईएफ द्वारा निवेश सुविधा के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए सार्वजनिक निवेश कोष (पीआईएफ) में इंडिया डेस्क के शुभारंभ की सराहना की। उन्होंने पाया कि उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का काम भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी को रेखांकित करता है, जो आपसी आर्थिक विकास और सहयोगी निवेश पर केंद्रित है।

अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित सऊदी–भारत निवेश मंच के परिणामों और दोनों देशों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच इसके द्वारा प्राप्त सक्रिय सहयोग की सराहना की। उन्होंने सऊदी अरब में भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश गतिविधियों के विस्तार की भी सराहना की और आपसी निवेश बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भूमिका की सराहना की। दोनों पक्षों ने इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरब के निवेश मंत्रालय के बीच द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने पर सहयोग के ढांचे को सक्रिय करने की सराहना की। दोनों पक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की सुविधा देने पर सहमत हुए, जिससे आपसी विकास और नवाचार में योगदान मिलेगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में, भारतीय पक्ष ने वैश्विक तेल बाजारों की स्थिरता बढ़ाने और वैश्विक ऊर्जा बाजार की गतिशीलता को संतुलित करने के लिए सऊदी अरब के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने वैश्विक बाजारों में सभी ऊर्जा स्रोतों के लिए आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। वे ऊर्जा क्षेत्र में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर सहमत हुए, जिसमें कच्चे तेल और एलपीजी सहित इसके डेरिवेटिव की आपूर्ति, भारत के रणनीतिक रिजर्व कार्यक्रम में सहयोग, विनिर्माण और विशेष उद्योगों सहित रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाएं, हाइड्रोकार्बन, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के अभिनव उपयोग, जिसमें दोनों देशों के बीच विद्युत अंतर्संबंध के लिए विस्तृत संयुक्त अध्ययन पूरा करना, ग्रिड स्वचालन, ग्रिड कनेक्टिविटी, विद्युत ग्रिड सुरक्षा और लचीलापन, और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में विशेषज्ञता का आदान–प्रदान करना और अपनी परियोजनाओं को लागू करने में दोनों पक्षों की कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना शामिल है।

हरित/स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर जोर दिया, जिसमें मांग को प्रोत्साहित करना, हाइड्रोजन परिवहन और भंडारण प्रौद्योगिकियों का विकास करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए विशेषज्ञता और अनुभवों का आदान–प्रदान करना शामिल है। दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं और परियोजनाओं को विकसित करने,

कंपनियों के बीच सहयोग को सक्षम बनाने, ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और इमारतों, उद्योग और परिवहन क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत को तर्कसंगत बनाने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर काम करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया।

जलवायु परिवर्तन के संबंध में, दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते के सिद्धांतों का पालन करने के महत्व की पुष्टि की और स्रोतों के बजाय उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु समझौतों को विकसित और लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय पक्ष ने सऊदी अरब द्वारा "सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव" और "मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव" की शुरूआत की सराहना की और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने उत्सर्जन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में सर्कुलर कार्बन अर्थव्यवस्था का उपयोग करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर सर्कुलर कार्बन अर्थव्यवस्था के अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए संयुक्त सहयोग के महत्व पर बल दिया। सऊदी अरब साम्राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक सूर्य–एक विश्व–एक ग्रिड, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) और पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल (एलआईएफई) और वैश्विक हरित ऋण पहल जैसी अग्रणी पहलों के माध्यम से वैश्विक जलवायु कार्रवाई में भारत के योगदान की सराहना की।

जलवायु परिवर्तन के संबंध में, दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते के सिद्धांतों का पालन करने के महत्व की पुष्टि की और स्रोतों के बजाय उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु समझौतों को विकसित और लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है; और सऊदी अरब 2023–2024 में भारत का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होगा। दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय व्यापार में विविधता लाने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस संबंध में, दोनों पक्ष व्यापार और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं को बढ़ाने और व्यापार और निवेश कार्यक्रम आयोजित करने के महत्व पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने भारत–जीसीसी एफटीए पर बातचीत शुरू करने की अपनी इच्छा दोहराई।

सामरिक भागीदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में रक्षा संबंधों को गहरा करने की सराहना की, और सामरिक भागीदारी परिषद के तहत रक्षा सहयोग पर एक मंत्रिस्तरीय समिति के गठन का स्वागत किया। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में पहली बार भूमि सेना अभ्यास सदा तनसीक, नौसेना अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी के दो दौर, कई उच्च स्तरीय यात्राओं और प्रशिक्षण आदान–प्रदान जैसे कई 'पहली बार' सहित अपने संयुक्त रक्षा सहयोग की वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सितंबर 2024 में रियाद में आयोजित रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की छठी बैठक के परिणामों का स्वागत किया, जिसमें तीनों सेनाओं के बीच स्टाफ–स्तरीय वार्ता की शुरुआत का उल्लेख किया गया। दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।

सुरक्षा क्षेत्रों में प्राप्त निरंतर सहयोग को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने बेहतर सुरक्षा और स्थिरता के लिए इस सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने साइबर सुरक्षा, समुद्री सीमा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय अपराध, नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया।

22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस संदर्भ में, दोनों पक्षों ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि यह मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। वे इस बात पर सहमत हुए कि किसी भी कारण से किसी भी आतंकी कृत्य का कोई औचित्य नहीं हो सकता। उन्होंने आतंकवाद को किसी विशेष जाति, धर्म या संस्कृति से जोड़ने के किसी भी प्रयास को खारिज

कर दिया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ़ लड़ाई और आतंकवाद के वित्तपोषण में दोनों पक्षों के बीच उत्कृष्ट सहयोग का स्वागत किया। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद की निंदा की और सभी देशों से दूसरे देशों के खिलाफ़ आतंकवाद के इस्तेमाल को अस्वीकार करने, जहां भी आतंकवाद का बुनियादी ढांचा मौजूद है, उसे नष्ट करने और आतंकवाद के अपराधियों को तुरंत न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया। दोनों पक्षों ने दूसरे देशों के खिलाफ़ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए मिसाइलों और ड्रोन सहित हथियारों तक पहुंच को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे सहयोग और वर्तमान तथा भविष्य के स्वास्थ्य जोखिमों तथा स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के प्रयासों पर चर्चा की। इस संदर्भ में, उन्होंने दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। भारतीय पक्ष ने नवंबर 2024 में जेद्दा में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए सऊदी अरब साम्राज्य को बधाई दी। भारतीय पक्ष ने सऊदी अरब में भारतीय दवाओं के संदर्भ मूल्य निर्धारण और फास्ट ट्रैक पंजीकरण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण द्वारा की गई पहलों का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को और पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाए जाने का भी स्वागत किया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, सेमी–कंडक्टर आदि जैसे नए और उभरते क्षेत्रों सहित प्रौद्योगिकी में सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। डिजिटल शासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, दोनों पक्ष इस क्षेत्र में सहयोग की संभावना तलाशने पर सहमत हुए। उन्होंने विनियामक और डिजिटल क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और सऊदी अरब साम्राज्य के संचार, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर भी संतोष व्यक्त किया।

इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित अंतरिक्ष सहयोग पर समझौता ज्ञापन अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष यान, भू प्रणालियों का उपयोग; अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग; अनुसंधान और विकास; शैक्षणिक जुड़ाव और उद्यमिता शामिल हैं।

दोनों पक्षों ने विरासत, फिल्म, साहित्य और प्रदर्शन और दृश्य कला जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से सऊदी अरब साम्राज्य और भारत गणराज्य के बीच सांस्कृतिक सहयोग के विकास पर ध्यान दिया। सामरिक भागीदारी परिषद के तहत पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग पर एक मंत्रिस्तरीय समिति का निर्माण इस साझेदारी को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दोनों पक्ष क्षमता निर्माण और सतत पर्यटन के माध्यम से पर्यटन में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। उन्होंने मीडिया, मनोरंजन और खेल में विभिन्न अवसरों के विस्तार पर भी ध्यान दिया, जिसे दोनों देशों के बीच लोगों के बीच मजबूत संबंधों द्वारा समर्थित किया गया।

दोनों पक्षों ने उर्वरकों के व्यापार सहित कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे सहयोग की सराहना की। उन्होंने इस क्षेत्र में दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के निर्माण हेतु आपूर्ति की सुरक्षा, आपसी निवेश और संयुक्त परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक समझौतों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

षैक्षिक और वैज्ञानिक सहयोग में बढ़ती गति की सराहना की, नवाचार, क्षमता निर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देने में इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया। सऊदी पक्ष ने सऊदी अरब में अग्रणी भारतीय विश्वविद्यालयों की उपस्थिति के अवसरों का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने श्रम और मानव संसाधनों में सहयोग बढ़ाने और सहयोग के अवसरों की पहचान करने के महत्व पर भी जोर दिया।

सितंबर 2023 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री एचआरएच प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान अन्य देशों के साथ भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे के सिद्धांतों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को याद किया और गलियारे में परिकल्पित कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की आपसी प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है जिसमें

माल और सेवाओं के मार्ग को बढ़ाने और हितधारकों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और डेटा कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रेलवे और बंदरगाह संपर्क शामिल हैं। इस संबंध में, दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2023 में हस्ताक्षरित विद्युत अंतर्संबंध, स्वच्छ/हरित हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर समझौता ज्ञापन के तहत प्रगति का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच शिपिंग लाइनों में वृद्धि पर भी संतोष व्यक्त किया।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए जी20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों में दोनों देशों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने ऋण सेवा निलंबन पहल (डीएसएसआई) से परे ऋण उपचार के लिए सामान्य ढांचे के भीतर उनके बीच मौजूदा सहयोग की सराहना की, जिसका समर्थन रियाद शिखर सम्मेलन 2020 में जी20 नेताओं द्वारा किया गया था। उन्होंने पात्र देशों के ऋण को संबोधित करने के लिए आधिकारिक ऋणदाताओं (विकासशील देश ऋणदाताओं और पेरिस क्लब ऋणदाताओं) और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय के लिए मुख्य और सबसे व्यापक मंच के रूप में सामान्य ढांचे के कार्यान्वयन को बढ़ाने के महत्व पर बल दिया।

यमन में संकट के व्यापक राजनीतिक समाधान तक पहुंचने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयासों के लिए अपने पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। भारतीय पक्ष ने यमन के पक्षों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सऊदी अरब द्वारा की गई कई पहलों की सराहना की, तथा यमन के सभी क्षेत्रों में मानवीय सहायता की पहुंच प्रदान करने और उसे सुगम बनाने में इसकी भूमिका की भी सराहना की। सऊदी पक्ष ने यमन को मानवीय सहायता प्रदान करने में भारतीय प्रयास की भी सराहना की। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के अनुरूप जलमार्गों की सुरक्षा और सुरक्षा तथा नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के महत्व पर सहमति व्यक्त की।

यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौता हुए ....

अंतरिक्ष विभाग, भारत और सऊदी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत गणराज्य और स्वास्थ्य मंत्रालय, सऊदी अरब साम्राज्य के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

डाक विभाग, भारत और सऊदी पोस्ट कॉर्पोरेशन (एसपीएल) के बीच आवक विदेशी सतह पार्सल के लिए द्विपक्षीय समझौता।

भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (एनएडीए), भारत और सऊदी अरब डोपिंग रोधी समिति (एसएएडीसी) के बीच डोपिंग रोधी और रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।

दोनों पक्षों ने रणनीतिक भागीदारी परिषद की अगली बैठक आपसी सहमति से तय तिथि पर आयोजित करने पर सहमति जताई। दोनों देश अपने–अपने देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वे विभिन्न क्षेत्रों में संचार, समन्वय और सहयोग जारी रखेंगे।

यात्रा के अंत में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने और अपने साथ आए प्रतिनिधिमंडल के गर्मजोशी भरे स्वागत और उदार आतिथ्य के लिए क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद को हार्दिक धन्यवाद कहा और उनकी प्रशंसा भी की। उन्होंने सऊदी अरब के मैत्रीपूर्ण लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त कीं। महामहिम ने भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारत के मैत्रीपूर्ण लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर व विकास का दशक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में किए गए हमलों में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखने और प्रार्थना करने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरा देश मिथिला और बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार के विकास के उद्देश्य से हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिजली, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये पहल बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। उन्होंने महान कवि और राष्ट्रीय प्रतीक रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री मोदी ने कहा कि बिहार वह भूमि है, जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। उन्होंने महात्मा गांधी के इस दृढ़ विश्वास की ओर ध्यान दिलाया कि भारत का तीव्र विकास तभी संभव है जब इसके गांव मजबूत हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंचायती राज की अवधारणा इसी भावना में निहित है। उन्होंने कहा, "बीते दशक में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए गए हैं। पंचायतों को मजबूत बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले एक दशक में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ी हैं। "श्री मोदी ने बताया कि गांवों में 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंचायतों के डिजिटलीकरण से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों तक आसान पहुंच जैसे अतिरिक्त लाभ हुए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के दशकों बाद देश को एक नया संसद भवन मिला है, वहीं देश भर में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायतों के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा, ''पिछले एक दशक में पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है जिसका उपयोग गांवों के विकास के लिए किया गया है।''

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्राम पंचायतों के

सामने सबसे बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी है। उन्होंने इस बात पर अक्सर असहमति जताई कि कौन–सी भूमि आवासीय है, कृषि योग्य है, पंचायत के स्वामित्व वाली है या सरकारी स्वामित्व वाली है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस समस्या के समाधान के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे अनावश्यक विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने में मदद मिली है।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पंचायतों ने सामाजिक भागीदारी को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दलितों, महादलितों, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदायों की महिलाएं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने इसे सच्चा सामाजिक न्याय और वास्तविक सामाजिक भागीदारी बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिक भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। इस दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला कानून भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सभी राज्यों की महिलाओं को लाभ होगा और हमारी बहनों और बेटियों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।

भारत रेलवे, सड़क और हवाई अड्डों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अपनी कनेक्टिविटी को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार महिलाओं की आय बढ़ाने और रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है, श्री मोदी ने बिहार में 'जीविका दीदी' कार्यक्रम के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिसने अनेक महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को और मजबूत करेगा और देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य में योगदान देगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बीते एक दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने नई गति प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि गांवों में गरीबों के लिए घर, सड़कें, गैस कनेक्शन, पानी के कनेक्शन और शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों करोड़ रुपये आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिससे मजदूरों, किसानों, वाहन चालकों और दुकानदारों को लाभ हुआ है और उन्हें आय के नए रास्ते मिले हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे विशेष रूप से उन समुदायों को लाभ हुआ है जो पीढ़ियों से वंचित थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का उदाहरण दिया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में कोई भी परिवार बेघर न रहे और सभी के सिर पर पक्की छत हो। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अकेले बिहार में 57 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दलितों और पिछड़े तथा अति पिछड़े समुदायों जैसे पसमांदा परिवारों को दिए गए हैं। श्री मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में गरीबों को 3 करोड़ और पक्के घर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज बिहार में लगभग 1.5 लाख परिवार अपने नए पक्के घरों में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 15 लाख गरीब परिवारों को नए घरों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें बिहार के 3.5 लाख लाभार्थी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आज लगभग 10 लाख गरीब परिवारों को उनके पक्के घरों के लिए वित्तीय सहायता भेजी गई है, जिनमें बिहार के 80,000 ग्रामीण परिवार और 1 लाख शहरी परिवार शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, "बीता दशक, भारत के इंफ्रास्ट्रंक्चर के विकास का दशक रहा है।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रहक्चंर एक विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार, 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नल के पानी के कनेक्शन मिले हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ से अधिक घरों में बिजली पहुंच चुकी है और जिन लोगों ने कभी गैस चूल्हे पर खाना पकाने की कल्पना भी नहीं की थी, उन्हें अब गैस सिलेंडर मिल गए हैं। उन्होंने कहा, "यहां तक कि लद्दाख और सियाचिन जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी, जहां बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना मुश्किल है, 4जी और 5जी मोबाइल कनेक्शन अब स्थापित हो चुके हैं, जो देश की वर्तमान प्राथमिकताओं को दर्शाता है।" प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एम्स जैसे संस्थान कभी दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित थे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब दरभंगा में एम्स की स्थापना की जा रही है और पिछले एक दशक में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। श्री मोदी ने झंझारपुर में एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के बारे में भी बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गांवों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए, देश भर में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनमें बिहार में 10,000 से अधिक मंदिर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र गरीब और मध्यम वर्ग के

लिए एक बड़ी राहत बन गए हैं, जो 80 प्रतिशत छूट पर दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब 800 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं, जिससे लोगों को चिकित्सा व्यय में 2,000 करोड़ रुपये की बचत हो रही है।

भारत की आत्मा पर एक निर्लज्ज हमला : मोदी

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आयुष्मान भारत योजना के तहत, बिहार में लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप इन परिवारों को हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई है।

"भारत रेलवे, सड़क और हवाई अड्डों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अपनी कनेक्टिविटी को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।" उन्होंने कहा कि पटना में मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं और देश भर के दो दर्जन से अधिक शहर अब मेट्रो सुविधाओं से जुड़ चुके हैं। उन्होंने पटना और जयनगर के बीच 'नमो भारत रैपिड रेल' सेवा शुरू करने की घोषणा की, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, और इस बात पर जोर दिया कि इस विकास से समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय के लाखों लोगों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ने बिहार में कई नई रेल लाइनों के उद्घाटन और शुभारंभ का भी जिक्र किया, जिसमें सहरसा और मुंबई के बीच आधुनिक अमृत भारत ट्रेन सेवा की शुरुआत पर प्रकाश डाला गया, जिससे श्रमिक परिवारों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार मधुबनी और झंझारपुर सहित बिहार के कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दरभंगा हवाई अड्डे से मिथिला और बिहार में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "ये विकास परियोजनाएं बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं।"

श्री मोदी ने कहा, "किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, यह रीढ़ जितनी मजबूत होगी, गांव उतना ही मजबूत होगा और परिणामस्वरूप, राष्ट्र भी मजबूत होगा।" उन्होंने मिथिला और कोसी क्षेत्रों में बाढ़ की लगातार चुनौतियों पर प्रकाश डाला, और कहा कि सरकार बिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस निवेश से बागमती, धार, बूढ़ी गंडक और कोसी जैसी नदियों पर बांध बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही नहरों का विकास किया जाएगा, जिससे नदी के पानी से सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा, "इस पहल से न केवल बाढ़ से संबंधित समस्याएं कम होंगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि हर किसान के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे।"

श्री मोदी ने कहा, "मिथिला का सांस्कृतिक प्रधान खाद्य पदार्थ मखाना अब सुपरफूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है।" उन्होंने बताया कि मखाना को जीआई टैग दिया गया है, जो इसे आधिकारिक तौर पर इस क्षेत्र के उत्पाद के रूप में प्रमाणित करता है। उन्होंने कहा कि मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। उन्होंने मखाना बोर्ड को लेकर बजट में की गई घोषणा पर भी प्रकाश डाला, जिससे मखाना किसानों की किस्मत बदलने की उम्मीद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिहार का मखाना अब सुपरफूड के रूप में अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार कृषि के साथ–साथ मत्स्य पालन में भी लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मछुआरों को अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है, जिससे मत्स्य पालन से जुड़े कई परिवारों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार में सैकड़ों करोड़ रुपये की

परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं।

22 अप्रैल को जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश व्यथित है और शोकाकुल परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उपचार करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने परिवारों को हुए भारी नुकसान पर प्रकाश डाला, जहां कुछ ने अपने बेटे, भाई या जीवन साथी खो दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित विभिन्न भाषायी और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से थे – कुछ बंगाली, कन्नड़, मराठी, ओडिया, गुजराती बोलते थे, और कुछ बिहार से थे। यह बताते हुए कि कारगिल से कन्याकुमारी तक, इस हमले पर पूरे देश में समान रूप से दुख और आक्रोश है, श्री मोदी ने कहा कि यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर एक निर्लज्ज हमला था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, "इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी।" उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के बचे हुए गढ़ों को खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा, ''140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंकवाद के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी।''

प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से घोषणा करते हुए कहा कि भारत हर आतंकवादी, उसके आकाओं और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें दंडित करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत उन्हें धरती के कोने–कोने तक खदेड़ देगा। उन्होंने जोर देकर कहा, "आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी और आतंकवाद को दंडित किया जाएगा। न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इस संकल्प के प्रति दृढ़ है।" उन्होंने यह भी कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति इस मुश्किल समय में भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने विभिन्न देशों के लोगों और नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस मुश्किल समय में भारत का साथ दिया।

श्री मोदी ने कहा, "तेजी से विकास के लिए शांति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण शर्त है।" उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित बिहार आवश्यक है। उन्होंने यह कहते हुए अपने संबोधन का समापन किया कि बिहार में विकास सुनिश्चित करने और राज्य के हर वर्ग और हर क्षेत्र तक प्रगति का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, श्री जीतन राम मांजी, श्री गिरिराज सिंह, श्री चिराग पासवान, श्री नित्यानंद राय, श्री राम नाथ ठाकुर, डॉ. राज भूषण चौधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए।

प्रधानमंत्री ने बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपये की लागत से रेल अनलोडिंग सुविधा वाले एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। इससे आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने और थोक एलपीजी परिवहन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

क्षेत्र में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने 1,170 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत बिहार में बिजली क्षेत्र में 5,030 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। देश भर में रेल संपर्क बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और पिपरा और सहरसा तथा सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने सुपौल पिपरा रेल लाइन, हसनपुर बिथान रेल लाइन और छपरा और बगहा में 2–लेन वाले दो रेल ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। उन्होंने खगड़िया –अलौली रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास होगा। प्रधानमंत्री ने दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के अंतर्गत बिहार के 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत लगभग 930 करोड़ रुपये का लाभ वितरित किया।प्रधानमंत्री ने पीएमएवाई–ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे और देश भर के 10 लाख पीएमएवाई–जी लाभार्थियों को किस्तें जारी कीं। उन्होंने बिहार में 1 लाख पीएमएवाई–जी और 54,000 पीएमएवाई–यू घरों में गृह प्रवेश के अवसर पर कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपीं।

कांग्रेस ने मुसलमानों के विकास के लिये कोई कार्य नहीं किया : अग्रवाल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की शुरू से रणनीति रही कि देश का मुसलमान डरा रहे व हिन्दू विरोध में खड़ा रहे और वोट बैंक की तरह भाजपा के विरोध में कांग्रेस के लिए लगातार वोट करता रहे। कांग्रेस ने कभी प्रयास नही किया कि मुस्लिम आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत हो। उन्होंने कहा कि 2005 में कांग्रेस सरकार ने सच्चर कॅमेटी गठित की और 2006 में कॅमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट में आया कि देश का मुसलमान आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा है व सामाजिक रूप से अलग–थलग है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नही किया जिससे मुसलमानों का आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक जीवन बेहतर हो सके। बस एक बयान दिया कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि मैं मानता हूं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। यही काम मोदी जी ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 31 फीसदी मकान मुस्लिमों को मिले। उज्जवला योजना में 37 प्रतिशत निःशुल्क गैस कनेक्शन मुस्लिम महिलाओं को मिले। मुद्रा योजना में 36 फीसदी लोन मुस्लिम परिवारों को मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 33 प्रतिशत मुस्लिमों को मिला है। स्किल इंडिया में 22 फीसदी, प्रधानमंत्री जनकल्याण योजना में 33 फीसदी मुस्लिमों को योजना का लाभ मिला। जबकि देश में मुस्लिमों की जनसंख्या 15 फीसदी है।

राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि सच्चर रिपोर्ट में लिखा कि देश में सन 2006 में 4,50000 वक्फ की संपत्तियां है। जिनका कुल रकवा 06 लाख एकड़ है। इस भूमि का हजार की दर से अगर 10 फीसदी लाभ लगा दिया जाए तो 2006 में वक्फ की संपत्तियों से 12 हजार करोड़ की आय होनी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ 163 करोड़ की आय होती है। बाकि रूपया कहां जा रहा है। इस पर सच्चर कॅमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जितने भी मुतवल्ली बनाए गए थे, वह वक्फ संपत्तियों के मालिक बन गए है और उन्होंने वक्फ संपत्तियों को लूट डाला है। जिन संपत्तियों का स्वरूप नही बदला जा सकता था उनमें बड़े अपार्टमेंट, होटल और कॉलेज बना दिए गए। यह भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड के सदस्यों और वक्फ बोर्ड के सीईओ के द्वारा मिलकर किया गया है। सच्चर कॅमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार को वक्फ की लूट बंद करना चाहिए। जो अतिक्रमण हुए है उन्हें खाली कराना चाहिए। भ्रष्टाचार करने वाले मुतवल्लियों और वक्फ सदस्यों सजा देनी चाहिए।

श्री अग्रवाल ने कहा कि संशोधन से पूर्व अधिनियम की धारा 40 कहती थी कि अगर वक्फ बोर्ड को महसूस होता है कि कोई जमीन वक्फ की है या वक्फ की हो सकती है तो संबंधित जमीन के मालिकान को नोटिस दिए बिना वक्फ बोर्ड के द्वारा कार्यवाही व जांच करके उसको वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाता था। पीड़ित पक्ष को सुनने का अवसर भी नहीं था। वक्फ बोर्ड की सूचना पर एसडीएम जमीन के मालिक का नाम काटकर वक्फ बोर्ड का नाम दर्ज कर लेता था। खाता न वही जो वक्फ कहे वही सही। भारतीय संविधान की धारा 14 में लिखा हुआ है कि न्याय पाने का अधिकार सभी को है। लेकिन कांग्रेस ने वक्फ कानून की आड़ में ऐसा कानून बनाया कि वक्फ किसी की भी संपत्ति लूटता तो उसे न्याय का अधिकार भी नही मिल सकता था। 2006 में वक्फ की कुल सम्पत्तियां 04 लाख 50 हजार थी, जिनका रकवा 06 हजार एकड़ था वह 2025 में बढ़कर 08 लाख 72 हजार हो गई और उनका रकवा 37 लाख 94 हजार एकड़ हो गया। कर्नाटक अल्पसंख्यक कमीशन के चेयरमैन अनवर मालपाणी ने वक्फ कॅमेटी पर अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कर्नाटक में 54 हजार एकड़ जमीन में से 29 हजार एकड़ जमीन कांग्रेस के कर्नाटक के नेताओं ने बेच दी है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीएम

इब्राहिम, तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहमान खान, कांग्रेस के पूर्व सांसद इकबाल, पूर्व रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं के नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वक्फ संशोधन अधिनियम–2025 के द्वारा सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए वक्फों के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया। वक्फ संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान है कि वक्फ की एक–एक इंच जमीन ऑन रिकार्ड की जाएगी। कितना रकवा है किसने कब्जा किया है यह बताना होगा। यही विपक्ष सहित तमाम खुद को मुस्लिम रहनुमा बताने वालों के विरोध की मुख्य वजह है। वक्फ बोर्ड की आढ में लूट करने वाला, जिनके लिए मोदी जी भू–माफिया शब्द का प्रयोग किया है। इनके सत्य को जनता तक पहुंचाने का काम करना है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि कार्यशाला में प्रशिक्षण के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम – 2025 की आवश्यकता और इसके गरीबों को मिलने वाले लाभ का सत्य लेकर हमें जनसंवाद के लिए लोगों के बीच पहुंचना है। वक्फ कानूनों की आड़ में भ्रष्ट लोगों के द्वारा लोगों की संपत्तियों को अवैध तरीकें से कब्जा किया जाता था। इस प्रकार के प्रकरणों की संख्या अदालतों में भी बढ़ती रही है। यह हम सभी के साथ देश के लिए चिन्ता का बड़ा विषय था। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में नीतिगत अभाव रहा है। महिलाओं की भागीदारी में कमी रही। किसी भी संपत्ति को बिना किसी तार्किक आधार के वक्फ की संपत्ति घोषित कर बड़े स्तर पर कब्जा करने का काम किया गया। वक्फ संशोधन अधिनियम से वक्फ संपत्तियों के लेखा–जोखा एवं निरीक्षण की प्रक्रिया भी प्रारम्भ होगी। वक्फ प्रबंधन में प्रशासनिक अक्षमता तथा केन्द्रीय वक्फ बोर्ड व राज्य वक्फ बोर्डो में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना होने के कारण समाज के कमजोर वर्ग व महिलाओं को इसका लाभ नही मिल पाया।

श्री चौधरी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक–2025 कमजोर वर्ग व महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत करने में सहायक साबित होगा। यह विधेयक विरासत एवं व्यक्तिगत संपत्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा। मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। विपक्ष का एजेंडा नकारात्मक प्रचार से लोगो को भ्रमित करने का है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प सबका साथ–सबका विकास व सबका विश्वास है और यही संकल्प केन्द्र सरकार की प्रत्येक योजना व निर्णय में परिलक्षित होता है।

श्री चौधरी ने कहा कि विपक्ष के हर नकारात्मक दुष्प्रचार का जवाब हमें जनता के बीच लेकर पहुंचना है। जन–जागरण के माध्यम से अलग–अलग समूहों के बीच वक्फ संशोधन अधिनियम–2025 से अल्पसंख्यक समाज के हित में होने वाले कार्यों को लेकर सम्पर्क व संवाद स्थापित करना है। भाजपा सबसे बड़ा राजनैतिक दल है और भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस बिल को लेकर घर–घर और जन–जन तक पहुंचेंगे।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के सहारे 60 साल कांग्रेस ने राज किया। मुसलमानों को गरीब, अशिक्षित व बेरोजगार बनाए रखा। कांग्रेस ने मुसलमानों के बीच हिन्दुओं से लड़ते रहो और कांग्रेस को वोट देते रहो की नीति पर लम्बे समय तक काम किया। कांग्रेस और कांग्रेस कम्पनी मुसलमानों को भाजपा का भय दिखाकर वोट बैंक की राजनीति करती है। विपक्ष की इन साजिशों के बावजूद भी भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज केन्द्र में भाजपा की सरकार है और इसके साथ ही 70 फीसदी हिस्से में भाजपा व भाजपा गठबंधन की सरकारें है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें मिलने से कोई रोक नही सकता है।

श्री मौर्य ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार बनी और सबका साथ–सबका विकास–सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर काम शुरू हुआ। हमें वक्फ संशोधन अधिनियम की वास्तविकता को लेकर मुसलमानों के बीच पहुंचना है। उन्होंने कहा कि देश में मच रहे बवाल के पीछे कांग्रेस, सपा और अंर्तराष्ट्रीय शक्तियां है। कांग्रेस ने दूध में नींबू निचोड़ने का काम किया है और हिन्दू व मुसलमानों के बीच झगड़ा पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं नही है जबकि समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूली हुई है। सपा चाहती है कि अगड़े, पिछड़े व दलित आपस में लड़ते रहे। हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है।

उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस का नेतृत्व जिन हाथों में था, वह चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। जब कोई कार्यकर्ता अपने परिश्रम से

राजनीति में बडे पदों पर पहुंचता तो वह जनता के दर्द को भी समझता है और जनता के अधिकारों के साथ खड़ा होता है। कांग्रेस ने आजादी के बाद व देश के बंटवारे के बाद मुसलमानों को वोट बैंक की तरह उपयोग किया।

श्री पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी वर्गों की तरह मुसलमानों को भी आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक रूप से मजबूत करते हुए विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया गया और बिना वोट की राजनीति के सबका साथ, सबका विकास की नीति पर किया गया। कांग्रेस ने मुसलमानों को बिरयानी में पडे हुए तेजपत्ते की तरह उपयोग किया, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया और राजनीति की बिरयानी पकने के बाद तेजपत्ते को निकाल कर बाहर फेंक दिया। हमें वक्फ संशोधन अधिनियम के साथ ही विपक्ष के खतरनाक मंसूबों को भी जनता के दरबार में लेकर जाना है।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ संशोधन अधिनियम के संसद में पास होने के बाद से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल देश में भ्रम फैला रहे है। इस कार्यशाला के माध्यम से हमें पूरी जानकारी के साथ लोगों के बीच जाकर भ्रम को दूर करके सत्य से अवगत कराना है। हमें समाज के अंदर बताना है कि कैसे पसमांदा समाज, पिछड़े वर्ग, सिख, इसाई, अनुसूचित वर्ग सहित आमजनता की संपत्तियों पर भी कब्जा था। इस बिल के पास होने के बाद जिसका जो हक है उसको वह हक मिलेगा।

श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सम्पर्क व संवाद के माध्यम से हमें वक्फ संशोधन अधिनियम को जनता के बीच लेकर जाना है। इसके लिए संगठन ने चरणबद्ध तरीकें से कार्यक्रम तय किए है। प्रदेश की कार्यशाला के पश्चात 21 और 22 अप्रैल में क्षेत्र स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला स्तर की कार्यशालाएं 23 व 24 अप्रैल को जिला केन्द्रों पर आयोजित की जायेंगी।

श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वक्फ सुधार जन–जागरण अभियान के तहत 25 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुस्लिम स्कॉलर, मौलाना, दरगाहों के संचालक, शायर, अल्पसंख्यक विद्यालयों के संचालक, मुस्लिम उद्यमी, चिकित्सक, प्रोफेसर, खिलाड़ी तथा सोशल मीडिया के प्रभावी इन्फ्लुएंसर के बीच टाउन हॉल कार्यक्रम के माध्यम से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की आवश्यकता पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 28 व 29 अप्रैल को महानगर एवं जिला स्तर पर भी टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अभियान के तहत नागरिक संवाद के कार्यक्रम 02 मई व 03 मई को आयोजित किये जायेंगे। नागरिक संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ छोटी–छोटी बैठकों में संवाद करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी घर–घर सम्पर्क के माध्यम से भी वक्फ संशोधन अधिनियम–2025 को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेगी। 26, 27 व 28 अप्रैल को डोर–टू–डोर कैम्पन में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अल्पसंख्यक वर्ग के बीच में पहुंचकर संवाद करेंगे। इसके साथ ही पत्रक भी घर–घर पहुंचाने का काम किया जाएगा।

श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिलेगा कैम्पन के साथ सम्पर्क व संवाद करेंगे। 30 अप्रैल व 01 मई को महिला सम्पर्क व सम्मेलन के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। महानगरों एवं जिला स्तर पर महिला मोर्चा के द्वारा सम्मेलन आयोजित करके संवाद किया जाएगा। 27 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के पश्चात अल्पसंख्यक वर्ग के बीच सम्पर्क भी करना है। युवा मोर्चा 04 व 05 मई को जनसंवाद के कार्यक्रम आयोजित करके वक्फ संशोधन अधिनियम–2025 को लेकर अल्पसंख्यक वर्ग के बीच पहुंचेगा।

भारतीय जनता पार्टी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के माध्यम से प्रदेश में वक्फ संसोधन विधेयक का सत्य लेकर जन संवाद करेगी। लखनऊ के भागीदारी भवन में आयोजित कार्यशाला को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य व श्री ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने संबोधित किया। कार्यशाला में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अभियान के प्रदेश संयोजक श्री त्रयम्बक त्रिपाठी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी, श्री असीम अरूण, श्री जसवंत सैनी, प्रदेश मंत्री श्री शिवभूषण सिंह तथा अभियान के सहसंयोजक श्री अखिलेश बाजपेई उपस्थित रहे। कार्यशाला का संचालन अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली ने किया। कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, अभियान के जिला संयोजक व सहसंयोजक, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी, मीडिया सहप्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता, मोर्चो के प्रदेश अध्यक्ष, आईटी एवं सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक व सहसंयोजक सम्मिलित रहे।

वक्फ सम्पत्ति के मुतवल्ली मालिक कैसे?

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने राज्य मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता मे कहा कि :– 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि देश में 4 लाख 50 हज़ार वक्फ की सम्पत्ति है जिसमें वक्फ जमींन का रकबा 6 लाख एकड़ है। अगर इस जमींन का उपयोग किया जाता है तो 10 प्रतिशत के हिसाब से 12 हजार करोड़ रूपये की वक्फ संपत्तियों से आय होती। लेकिन आय हुई केवल 163 करोड़ रूपये। वक्फ संपत्तियों के लिए अधिकांश मुतवल्ली जो बनाए गए थे मालिक बन गए।

वक्फ संपत्तियां अल्लाह को दी गई है, जो कभी बेची नहीं जा सकती थी। ना उनके स्वरूप में बदलाव किया जा सकता था।लेकिन मुतवल्लियों ने वक्फ संपत्तियों पर या तो उनके परिवार का या नजदीकी लोगों का नाम चढ़ा दिया। जिन संपत्तियों का किराया एक लाख हो सकता था उन्हें 5000 के किराये पर दे दिया। कुछ धनराशि काले धन के रूप में चुपचाप ले ली गई। यह सब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हिस्सा है। सच्चर कमेटी ने सरकार से कहा कि मुतवल्लियों और भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित किया जाय।

जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया है उसे खाली कराइये। वक्फ संपत्तियों का उपयोग करके गरीब मुसलमानों के जीवन को बेहतर बनाईये। 2006–2014 तक देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मानने की बात तो दूर कांग्रेस सरकार ने 2013 में इस वक्फ अधिनियम में एक नया संशोधन लाई और वक्फ संपत्तियों की लूट में और छूट दे दी। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। मैं अपनी योजनाएं गरीबों के हित में लागू करूगा। देश में 15 प्रतिशत मुस्लिम समाज की जनसंख्याा थीं। प्रधानमंत्री आवास के 31 प्रतिशत आवास मुस्लिम समाज को मिले। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 37 प्रतिशत निःशुल्क गैस कनेक्शन मुस्लिम समाज को मिले। मुद्रा योजना में 36 प्रतिशत लाभ मुस्लिम समाज को मिला। किसान सम्मान निधि के 33 प्रतिशत लाभ मुस्लिम समाज को मिले।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस गठबंधन वाली यूपीए सरकार ने कूडे के ढेर में फेंक दिया था।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार जो कुछ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में अपेक्षाए की गई थी उनका वक्फ बिल में संशोधन कर दोनो सदनों में पारित कराया। बिल पर 12 घंटे लोकसभा व 14 राज्यसभा में बहस हुई। इससे पहले भारत के इतिहास में इतनी बड़ी बहस नहीं हुई थी। इसके बाद यह अधिनियम पास हुआ।

इस अधिनियम की टैग लाइन है गरीबों का हक सिर्फ और सिर्फ गरीबों को मिले।

जिन्होंने कब्जे किये उन्हें कब्जे खाली करने होगें। जो बिल्डिंग है उन्हें आज के हिसाब से किराया देना होगा।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार से अपेक्षा करती थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कूड़े से निकाला और अध्ययन किया।

वक्फ बोर्ड के द्वारा जो लूट हुई है, उसे कांग्रेस ने किया है, मुस्लिम नेताओं ने किया है या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों ने किया है मोदी जी जिद्दी हैं उनके कब्जे को हटवाकर मानेंगे। आज वह विरोध कर रहें और मुसलमान को भड़का रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं अपने अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के साथ कस्बे में घर–घर जाने वाली है। जिन मुस्लिम रहनुमाओं ने जमीनों पर कब्जा किया है उनको बेनकाब करने वाली है। अपने कार्यकर्ताओं को अभी हम प्रशिक्षित कर रहे हैं।

पूरे देश में बड़ी–बड़ी गोष्ठियां करेंगे, छोटी–छोटी बैठक करेंगे। मुस्लिम समाज के घर–घर में पर्चा बाटेंगे। वक्फ अधिनियम मुसलमान को जीवन को कैसे खूबसूरत करने वाला है यह मुस्लिम समाज को बताएंगे।

जिहादी युद्ध की विचारधारा

हृदयनारायण दीक्षित

दुनिया अनेक युद्धों की गिरफ्त में है। कहीं युद्ध जारी है और कहीं वैश्विक तनाव के कारण युद्ध की संभावनाएं हैं। भारत में कश्मीर के पहलगाम में हृदय विदारक जिहादी हमला हुआ है। इसे युद्ध कहना ज्यादा उचित होगा। यह स्वतंत्र घटना नहीं है। इसके पहले भी अनेक ऐसे ही हमले हुए हैं। क्या मुंबई के ''26/11'' के नाम से चर्चित नवंबर 2008 के हमले को केवल आतंकवादी घटना कहा जा सकता है? यह दरअसल अपने ढंग के जिहादी युद्ध का ही रौद्र रूप है।

इस्लामिक विचारधारा के अंतरराष्ट्रीय विद्वान प्रोफेसर डेनियल पाइप (इन दि पाथ ऑफ गॉड, पृष्ठ 46) ने कहा था जिहाद एक अंतरराष्ट्रीय धारणा है। यह संसार के इंसानों को दो भागों में बांटती है। एक दारुल हरब, जहां इस्लाम का राज नहीं है। दूसरा दारुल इस्लाम जहां इस्लामी राज्य है। जिहाद इन लोगों के मध्य निरंतर युद्ध की स्थिति है। इस्लामी चिंतन के विद्वान मौलाना मौदूदी कहते हैं, "दीन की स्थापना के मकसद से हुकूमत पर कब्जा करने के लिए युद्ध की इजाजत है।" (इस्लामिक लॉ एंड कांस्टीट्यूशन, पृष्ठ 177, खुर्शीद अहमद)

दरअसल इस्लामी चिंतन में युद्ध एक अनिवार्य धारणा है। कुरान (2/216) में कहा गया है कि, "तुम पर युद्ध अनिवार्य किया गया है।" यह भी हिदायत है, "जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वह जिंदा हैं। कुरान (8.74) में कहा गया है, "जो अल्लाह के मार्ग में लड़ेगा, वह मारा जाय या विजयी हो, हम शीघ्र ही उसको बड़ा बदला देंगे। जिहादी युद्ध के लिए अपने जांबाज समर्थक तैयार करने के लिए ऐसी विचारधारा उपयोगी है। लगातार युद्ध की इस्लामी धारणा आतंकवादी समर्थक विचारकों के शोध का नतीजा नहीं है। इस्लामी विद्वानों के तमाम लेख और विचार दुनिया के चिंतनशील लोगों के लिए बेचैनी है। दुनिया को इस्लाम में शामिल करना उनका लक्ष्य है। जिहादी आतंकवाद व्यवस्थित युद्ध का हिस्सा है।

भारतीय दर्शन में सत्य की विजय का आश्वासन है। 'सत्यमेव जयते' की घोषणा मुण्डकोपनिषद में है। मगर जीवन में सत्य की विजय प्रायः नहीं दिखाई पड़ती। संसार में शक्ति की विजय ही दिखाई पड़ती है। इसे भारतीय विचार में 'मत्स्य न्याय' कहा गया है और यूरोप में 'सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट'। छोटी मछली बड़ी मछली खा जाती है। बड़ी मछली को मछुआरे पकड़ लेते हैं। वन में शेर बलवान है। वह वनराज है। छोटे जीवों को बड़े जीव खा जाते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मतत्व का ज्ञान बलहीन को नहीं मिलता—नायेनात्मा बलहीन लाभ्यो। संसार कर्म क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र है। शक्ति की विजय भौतिक अध्ययन के निष्कर्ष हैं। सारी दुनिया के इतिहास में युद्धों के किस्से हैं। पिता शाहजहां को औरंगजेब द्वारा पीने का पानी न उपलब्ध कराने की घटना महत्वपूर्ण है। परिवार में भाई द्वारा भाइयों की हत्या के उदाहरण भी तमाम हैं। क्या युद्ध मानव जाति का स्वभाव है?

भारतीय चिंतन में शक्ति का महत्व है। श्रीराम विश्व

मानवता के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। स्वाभाविक महानायक हैं। गीता में श्रीकृष्ण श्रेष्ठ विभूतियों का उल्लेख करते हैं। कहते हैं, "ऋतुओं में बसंत मैं हूं। नदियों में गंगा मैं हूं। वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। शस्त्रधारियों में शस्त्रधारी श्रीराम मैं ही हूं।" श्रीराम के अनेक रूप हैं। लेकिन शस्त्रधारी श्रीराम की बात ही दूसरी है। भारतीय देव प्रतीकों में शस्त्रधारियों की संख्या कम नहीं है। परमवीर हनुमान वज्रधारी हैं। परशुराम फरसा धारण करते हैं। ऋग्वेद में रुद्र बिजलियां गिराते हैं। दुर्गा देवी अनेक शस्त्र धारण करती हैं। श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। वैदिक देवता इंद्र शस्त्र धारण करते हैं। भौतिकवादी दृष्टि से गीता का पूरा दर्शन युद्ध भूमि के तनाव की प्रेरणा है। अर्नाल्ड टायनबी ने **'दि स्टडी ऑफ हिस्ट्री'** में सभ्यताओं के जन्म की परिस्थितियों का विवेचन किया है। उन परिस्थितियों का भी विवेचन है, जिनमें सभ्यताओं का पतन होता है। डॉ. राधाकृष्णन ने एक भाषण माला (1924) में कहा था कि, "सभ्यता मनुष्यों द्वारा आसपास की परिस्थितियों के साथ कठिन सम्बंधों में तालमेल बिठाने का परिणाम होती है।" टायनबी ने इस प्रक्रिया को 'चुनौती और प्रतिभावन' के ढंग की प्रक्रिया माना है। बदलती हुई परिस्थितियां समाजों के लिए चुनौती के रूप में सामने आती हैं और उनका सामना करने से भी सभ्यताओं का जन्म और विकास होता है।" अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के अनवरत प्रयत्न का नाम जीवन है। जब हम अपने आपको सफलतापूर्वक उनके अनुकूल ढाल लेते हैं, तब हम प्रगति कर रहे होते हैं और जब बर्बरता चुनौती देती है तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इसी भाषण माला में डॉ० राधाकृष्णन ने कहा है कि, "युद्ध अच्छे उद्देश्यों को पूरा करने के साधन है।" यहां कुछ उद्धरण दिए जाते हैं जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। नीत्शे का कथन है, "जो राष्ट्र दुर्बल और दयनीय होते जा रहे हैं, उनके लिए, युद्ध को औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है।" उसने कहा, "पुरुषों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाए। बाकी सब बातें बेहूदा हैं।" यदि उद्देश्य अच्छा हो, तो उसके कारण युद्ध तक को भला समझा जा सकता है। अच्छे युद्ध के कारण किसी भी उद्देश्य को भला समझा जा सकता है।" गीता में, **"परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्"**—युद्ध का उद्देश्य है।" रस्किन का कथन है, "महान राष्ट्रों ने अपने विचारों की सत्यता और सफलता को युद्धों में ही पहचाना है। युद्धों द्वारा वे राष्ट्र पनपे और शांति द्वारा नष्ट हो गए।" युद्ध में उनका जन्म हुआ और शांति में वह मर गए।" मोल्टेक ने कहा, "युद्ध परमात्मा के संसार का आंतरिक अंग है, जो मनुष्य के सर्वोत्तम गुणों का विकास करता है। स्थाई शांति केवल एक स्वप्न है और वह भी कोई सुंदर स्वप्न नहीं।"

'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्'-युद्ध का उद्देश्य है। रस्किन का कथन है, महान राष्ट्रों ने अपने विचारों की सत्यता और सफलता को युद्धों में ही पहचाना है।

बर्नहार्डी ने घोषणा की युद्ध एक प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता है। यह मानव जाति के जीवन में एक अनिवार्य नियामक वस्तु है। युद्ध के अभाव में घटिया और चरित्रहीन जातियां स्वस्थ और सशक्त जातियों पर हावी हो जातीं और परिणाम स्वरुप पतन ही होता। युद्ध नैतिकता का एक अनिवार्य उपकरण है। यदि स्थितियों के कारण आवश्यकता हो, तो युद्ध करवाना न केवल उचित है, अपितु राजनीतिज्ञों का नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य भी है।" ओसवाल्ड स्पैंगलर लिखता है, "युद्ध उच्चतर मानवीय अस्तित्व का षाश्वत रूप है। राष्ट्रों का अस्तित्व ही केवल युद्ध करने के लिए है।" आर्थर कीथ ने 1931 में ऐबर्डीन विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा था, "प्रकृति अपने मानवीय उद्यान को छंटाई द्वारा स्वस्थ बनाए रखती है। युद्ध उसकी कतरनी है। हम उसकी सेवाओं के बिना काम नहीं चला सकते।" सभी राष्ट्रों में ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने युद्ध को शक्ति प्रदान करने वाले के रूप में स्तुति की है। कहा जाता है कि युद्ध से साहस, स्वाभिमान, निष्ठा और वीरता जैसे उच्च गुणों का विकास होता है। लेकिन भारत युद्ध प्रिय देश नहीं है। यह गाँधी, बुद्ध, विवेकानन्द व हेडगेवार का देश है।

हम पर युद्ध थोपा गया है। अब युद्ध का कोई विकल्प नहीं। राष्ट्र मर्माहत है। भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जवाबी कार्रवाई शुरू कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह प्रतिपल सजग व सक्रिय हैं। राजनाथ सिंह सेना की बैठकें कर रहे हैं। विपक्ष ने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। गीता के प्रवचन के अंत में संजय ने कहा, "यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। (गीता 18.78)—जहाँ श्रीकृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, उसी पक्ष की विजय सुनिश्चित है।"

हिन्दुओं पर आतंक की कुदृष्टि

मृत्युंजय दीक्षित

जब ऐसा प्रतीत होने लगा कि कश्मीर आतंकवाद के साए से निकलकर विकास और शांति के पथ पर आगे बढ़ रहा है तब ही पाकिस्तान ने अपने आतंकी संगठनों और कश्मीर में अपने बचे खुचे स्लीपर सेल की सहायता से एक बार फिर आतंक का नंगा नाच किया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हुआ उसने देश की नब्बे के दशक की डरावनी स्मृतियां ताज़ी कर दीं। हथियारबंद आतंकवादियों ने बैसरन पहुंचे हिन्दू पर्यटकों अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। हिन्दुओं से उनका धर्म पूछा, कलमा सुनाने को कहा, नीचे के कपड़े उतारकर मजहब जांचा और सिर में गोली मार दी। बिलखते हुए औरतों और बच्चों से कहा जाओ– मोदी को बताओ।

आतंकवादियों ने यह घृणित काम उस समय किया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस भारत में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर। आतंकवादियों ने हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए मंगलवार का दिन चुना जिसे हिन्दू बहुत पवित्र मानते हैं। आतंकवादी बॉडी कैमरा पहने हुए थे, उन्होंने हत्याओं का वीडियो भी बनाया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सोचा था कि ऐसा कुछ करके वो भारत को एक बार फिर अस्थिर कर देंगे लेकिन वो भूल गए कि अब भारत बहुत आगे बढ़ चुका है और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। घटना की सूचना आते ही प्रधानमंत्री सऊदी अरब से, गृह मंत्री से बात करते हैं और गृहमंत्री अमित शाह तत्काल श्रीनगर पहचंकर सुरक्षा समीखा बैठकें करते हैं, घटन स्थल पर जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ जाते हैं और एअरपोर्ट पर भी बैठक कर अद्यतन जानकारी लेते हैं । वित्तमंत्री अमेरिका से भारत निकल पड़ती हैं। उसी दिन कैबिनेट समिति की बैठक होती है और पाकिस्तान सम्बन्धी कूटनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। पहलगाम हिंदू नर संहार के प्रत्येक पीड़ित का शव सैनिक सम्मान के साथ घर पहुंचाया जा रहा है।

भारत सरकार ने पाकिस्तान को कूटनीतिक दृष्टि से कड़ा संदेश देते हुए 1960 का सिन्धु जल समझौता निलंबित कर दिया है, ज्ञातव्य है कि 1965 और 1971 के युद्ध में भी इसे निलंबित नहीं किया गया था। अटारी बार्डर बंद कर दिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करते हुए उनको 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है और भारत अपने नागरिकों को पाकिस्तान से वापस बुला रहा है। दूतावासों अधिकारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जा रही है। यही नहीं भारतीय सेनाओं को हाई एलर्ट कर दिया गया है । कश्मीर घाटी में भी आपरेशन आलआउट में तीव्रता लाई जा रही है। भारत के सभी प्रमुख राजनयिकों के साथ बैठक करके उन्हें भारत के पक्ष से अवगत करा दिया है। रूस, अमेरिका, इजराइल, इटली जैसे सभी प्रमुख राष्ट्रों ने भारत की आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) की नीति का समर्थन किया है।

प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में अत्यंत सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए चेतावनी दी है, कि इस घटना में शामिल तथा इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों की पहचान करके उनको दंड देने के लिए भारत धरती के किसी भी कोने में जाएगा। इस बार इन षड्यंत्रकारियों को ऐसा दंड मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। अब उनकी बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अंग्रेजी में दोहराते हुए, सम्पूर्ण विश्व को भी ये सन्देश दिया कि. भारत अब रुकने वाला नहीं है।

धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान तथा उसके आतंकी नेटवर्क में बेचैनी थी और ये लोग बड़ी वारदात को अंजाम देने का लगातार प्रयास कर रहे थे अंततः उमर अब्दुल्ला सरकार की सरकार वापस आने के बाद उनको यह मौका मिल ही गया। आतंकवादी गुट कश्मीर में लगातार बढ़ रहे पर्यटन से परेशान थे क्योंकि गरीब कश्मीरी मुसलमानों जिनमें गुज्जर, बकरवाल जैसे शिया मुस्लमान शामिल हैं उनसे उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा था। कश्मीर के गरीब परिवार पर्यटकों के आगमन से ही फलते –फूलते हैं और उनका जीवन –यापन चलता है। बीते दिनों घाटी में पर्यटकों के खिलाफ बयानबाजी की गई और पर्यटकों के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया गया इनमें सत्ताधारी ओमर अब्दुल्ला की पार्टी के लोग भी शामिल थे।

इस बार इन षड्यंत्रकारियों को ऐसा दंड मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी।

आज प्रधानमंत्री के अनथक प्रयासों से कश्मीर के हालात भले ही बदल रहे हों लेकिन स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से घटी के अब्दुल्ला और मुफ़्ती परिवारों के आस पास अभी भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनके मन में पाकिस्तान के प्रति प्रेम जागता रहता है और वो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। पहलगाम की आतंकी घटना जहाँ घटी वो स्थान अमरनाथ यात्रा के दौरान ही खुलता है, इस स्थान को टूर ऑपरेटर्स ने बिना सुरक्षा बलों को सूचित किये कैसे खोल दिया? वो कौन से टूर ऑपरेटर्स हैं? स्वाभाविक है ये हमला बिना स्थानीय लोगों की मिलीभगत के नहीं हुआ है और यही कारण है कि हमलावरों की खोज, पहचान के लिए अब तक 500 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।

आतंकी हमले में मारे गए मंजुनाथ की पत्नीपल्लवी राव, जिनसे आतंकियों ने कहा – जाओ मोदी को बताओ ने, रिपब्लिक चैनल पर अर्नब गोस्वामी से बात करते हुए कहा – "मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि भारत का सुनते ही आतंकियों को कांपना चाहिए" और मोदी जी ने पुरे विश्व के समक्ष इसकी घोषणा भी कर दी है। उधर मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे दल इस दुखद अवसर को भी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए भुना लेना चाहते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के दामाद राबर्ट्र वाड्रा ने हैरान करने वाला बयान दिया फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को महज एक हादसा बताकर हल्का करने का असफल प्रयास किया, इसी प्रकार का आपत्तिजनक बयान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दिया। इन सभी दलों के नेता और प्रवक्ता इस सत्य को झुठलाने में लगे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया है। यह लोग पाकिस्तान की निंदा तक नही कर पा रहे हैं, इनका व्यवहार पाकिस्तान व आंतकियों के लिए कवर फायर का काम कर रहा है।

समाज को संगठित एवं जागृत कर रहा है संघ : होसबाले

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लखनऊ विभाग की 'शाखा टोली का एकत्रीकरण' लखनऊ के आशियाना क्षेत्र स्थित स्मृति उपवन में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय सरकार्यवाह श्रीमान दत्तात्रेय होसबाले जी ने कहा, 'स्वयंसेवक शाखा के माध्यम से भारत के परम वैभव के लिये प्रतिदिन साधना कर रहे हैं।' साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि संघ 100 वर्षों से हिन्दू समाज को जागृत करता आ रहा है। संघ हिन्दुओं को सेवाभावी हिन्दू बनाने के साथ ही अकेले हिन्दू को शक्तिशाली एवं राष्ट्रीय हिन्दू बनाने का कार्य कर रहा है। हिन्दुओं को समरसता की धारा में लाने का कार्य संघ ने किया है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लखनऊ विभाग की 'शाखा टोली का एकत्रीकरण' कार्यक्रम

माननीय सरकार्यवाह जी ने कहा, पवित्र भगवा ध्वज के सम्मुख हम सभी यहां एकत्र हुए हैं, यह अपने कार्य पद्धति का हिस्सा है। संघ समय–समय पर अपने कार्यकर्ताओं को ठीक बनाये रखने एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिये इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। यह एक संगठनात्मक कार्यक्रम है। अपने संगठन को और मजबूत एवं सुसंगठित करने के लिये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इससे हमारे अंदर का स्वयंसेवकत्व बेहतर होता रहता है। इसकी तैयारी के लिये सभी ने अपनी–अपनी शाखा में कई दिनों तक मेहनत की है।

इसके आगे उन्होंने कहा कि हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं। हमने देश के लिये संकल्प लिया है। इस राष्ट्र को वैभव के शिखर एवं विकास के पथ पर ले जाने के लिये हम सदैव कार्यरत रहेंगे। ऐसा हम इसलिये करते हैं क्योंकि हम भारतवर्ष में जन्मे हैं। भारतवर्ष में जन्म लेने के लिये देवता भी तरसते हैं। इसलिये यहां जन्म लेना हमारा सौभाग्य है। ऐसे में हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम समाज और देश के प्रति अपने संकल्पनिष्ठ कर्तव्यों का निर्वहन करें। भारत के साहित्यकारों, वैज्ञानिकों एवं समाजसेवकों आदि ने इसे भारत तो बना दिया है। इस धरती को सँवार भी दिया है लेकिन इसे निरंतर उच्चकता की ओर ले जाने के लिये हमें भी अपने कर्तव्यों ने का निर्वहन करना होगा। माननीय सरकार्यवाह जी ने कहा, इस देश के लिये जिन महापुरुषों ने बलिदान दिया है, उन सबका हमें नाम तक याद नहीं रहता। ऐसे अनेक वीर हैं जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन को न्योछावर करतेहुये भारतीयता और धर्म की रक्षा की है। देश की खातिर अपने जीवन को समर्पित करने वाले ऐसे लोगों की तरह ही हमें भी अपना जीवन निर्वहन करना होगा। ऐसे महापुरुषों का कर्ज हम सब पर हैं। उन्होंने कहा, 'एक स्वंयसेवक का सपना होता है कि 'देश हमें सब कुछ देता है, हम भी देश को कुछ देना सीखें।'

माननीय सरकार्यवाह जी ने कहा कि सामाजिक काम तो पहले भी बहुत से लोगों ने किया है। ऐसे महापुरुषों से हम

प्रेरणा लेते हुये उन्हें नमन करते हैं। मगर इसमें विचारणीय है कि आरएसएस की भूमिका क्या है? इसे स्पष्ट करते हुये उन्होंने कहा कि संघ का कार्य है कि हर प्रकार का व्यक्ति अपने कार्य करते हुये देश–समाज के लिये कुछ न कुछ करे, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य है। संघ की विशेषता है कि एक ही समय में एक ही पद्धति से एक ही लक्ष्य के साथ स्वयंसेवक शाखा का कार्य रहे हैं। आप दक्षिण जाएं या उत्तम या पश्चिम या पूरब, सभी जगहों पर संघ की शाखा में जाकर देखने पर आप पाएंगे कि हर मौसम में संघ के स्वयंसेवक एक ही पद्धति से शाखा का आयोजन करते हैं। स्वयंसेवक शाखा के माध्यम से भारत के परम वैभव के लिये प्रतिदिन साधना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कुम्भा भारत की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक पहचान है। भारत और हिन्दुओं की पहचान है हाल में हुआ कुम्भ मेला। कोई इसे भारतीयता, कोई हिन्दुत्व तो कोई संस्कृति कहता है। संघ बीते 100 वर्षों से हिन्दू समाज को जागृत करता आ रहा है। इसीलिये संघ 100 वर्षों के पश्चात भी बढ़ता जा रहा है। हिन्दू समाज के साथ एक समस्या है कि इसे कोई महापुरुष आता है जगाता है। मगर वह फिर सो जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। हिन्दू समाज को बार–बार जागृत करना होता है। मगर वह बार–बार सो जाता है। ऐसा ही कार्य डॉ0 हेडगेवार जी ने किया है। संघ ने सदैव हिन्दुओं को जगाने का कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि आने वाले एक वर्ष में शाखा का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। इसके लिये संघ के पंच परिवर्तन के कार्य को हर मंडल, हर शाखा, हर टोली तक पहुंचाना होगा। यह कार्य करने के लिये हम सबको व्यापक स्तर पर तैयारी करनी होगी। स्वयंसेवक होने के नाते हम सबको समय देना होगा, हमें अनुशासन में रहना होगा। संघ का कार्य एक दृष्टि से साधना है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपना मूल्यांकन करता रहे। वह जो भी गलती करता है, उससे सबक लेता है। उन्होंने कहा कि संघ के लोग आपदा के समय में प्रथम पंक्ति में खड़े रहते हैं। हमें कार्यकारिणी, अभ्यास वर्ग आदि की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिये। हमारी गुणवत्ता की हर दिन परीक्षा होती है। यह आसान काम नहीं है। प्रतिदिन की शाखा देखने में तो आसान होती है मगर नियमित शाखा चलाना आसान नहीं है। जिंदगी भर संघ का कार्य करते हुये समाज का कार्य करने का हमने संकल्प लिया है। पूजा करने के समान ही संघ का कार्य भी पवित्र भाव से किया जाने वाला कार्य है। जब तक हिन्दू समाज है, हमें यह कार्य करना है।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संघ हिन्दू राष्ट्र नहीं बना रहा है। हिन्दू राष्ट्र तो पहले से है। संघ हिन्दुओं को सेवाभाव हिन्दू बनाने एवं अकेले हिन्दू को शक्तिशाली बनाने का कार्य कर रहा है। जातीय हिन्दू को राष्ट्रीय हिन्दू बनाने का कार्य कर रहा है। हिन्दुओं को समरसता की धारा में लाने का कार्य संघ ने किया है। भले ही जन्म से वह हिन्दू है मगर उसके आचरण, स्वभाव और विचार से उसे सम्पूर्ण हिन्दू बनाने का कार्य संघ कर रहा है। समाज के अंदर परिवर्तन लाने का कार्य हम कर रहे हैं। इसी प्रकार पर्यावरण की रक्षा करना, पौधे लगाना आदि यह सब समाज के गुणात्मक परिवर्तन हैं। संघ अपने कार्यों से समृद्धशाली एवं संगठित हिन्दू समाज बनाने का कार्य कर रहा है। संघ का हर स्वयंसेवक राष्ट्र की आराधना के लिये उदाहरण प्रस्तुत करे। समाज में बहुत सारे लोग अच्छा कार्य करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ मिलकर हमें उनका हृदय जीतते हुये कार्य करना चाहिये। ऐसा करने से भारत वैभवशाली होगा। फिर समृद्ध भारत विश्व में मंगल लाने का कार्य करेगा। भारत उठ रहा है, भारत उठेगा। भारत किसी को दास बनाने के लिये नहीं उठेगा, वह तो विश्व में मंगल लाने के लिये उठेगा।

बाबा साहब के सपनों को साकार करेगी भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव रामजी आम्बेडकर की जयन्ती को बूथ स्तर पर मनाकर बाबा साहेब को कृतज्ञ नमन किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने सहारनपुर के गढ़ी मलूक आम्बेडकर पार्क, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने लखनऊ पूर्वी विधानसभा के बूथ संख्या 292 पर तथा भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अभिनव प्रकाश व अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचन्द्र कनौजिया ने राजधानी लखनऊ के प्रेरणा स्थल पर संविधान निर्माता बाबा साहेब को पुश्पांजलि अर्पित कर नमन किया।

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बाबा साहेब को नमन करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, समता मूलक समाज के प्रणेता एवं भारत रत्न से सुसज्जित बाबा साहेब डा. भीम राव आम्बेडकर की जयन्ती पर उन्हें कोटि–कोटि नमन। बाबा साहेब न्याय व समता पर आधारित समाज के लिए सदैव प्रत्यनशील रहे। उनके महान व्यक्तिव एवं जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डा. भीमराव आम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार व मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। विगत एक दशक में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। एससी एक्ट को मजबूती मिली है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन योजना, उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाएं गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने में कारगर साबित हुई। गरीबों का उत्थान ही डा. भीमराव आम्बेडकर का सपना था।

श्री चौधरी ने कहा कि 2020 में मोदी सरकार ने डा. भीम राव आम्बेडकर की जयन्ती को केन्द्र सरकार के सभी विभागों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। भाजपा

का उद्देश्य डा. भीम राव आम्बेडकर जी के सपने को आगे बढ़ाना है। अगर कांग्रेस और उसका ईको सिस्टम यह सोचता है कि कांग्रेस द्वारा किये गए डा. भीम राव आम्बेडकर जी के अपमान को वह छुपा लेंगे और दुर्भावना पूर्ण झूठ फैलाकर अपने बुरे कर्मो को ढक लेगें तो यह उनकी भूल है। डा. भीम राव आम्बेडकर को कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने अपमानित करने का लगातार काम किया था और लगातार उन्हें दो–दो चुनाव हरवाने का काम भी किया। बाबा साहेब को भारत रत्न न देना, सेंट्रल हॉल में उनका चित्र नहीं लगने देना, यह सब कांग्रेस की बाबा साहेब के प्रति दुर्भावना है। श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बाबा साहेब डा. भीम राव आम्बेडकर जी से जुडे स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने बाबा साहेब डा. भीम राव आम्बेडकर की जयन्ती पर नमन करते हुए कहा कि सामाजिक समरसता के शिल्पकार, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डा. भीम राव आम्बेडकर की जयन्ती पर कोटिशः नमन। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरक है। बाबा साहेब ने सदैव गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के सामाजिक, आर्थिक उत्थान व राजनैतिक भागीदारी के लिए संघर्ष किया और उनको न्याय दिलाने का काम किया। बाबा साहेब का विचार था कि जब तक देश का गरीब, वंचित, शोषित वर्ग आर्थिक व सामाजिक रूप से संपन्न होकर देश के विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ेगा, तब तक देश सही अर्थों में उन्नति नहीं कर सकता है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार तथा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा सरकार की प्रत्येक योजना गरीब, वंचित, शोषित व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक उन्नति के लिए समर्पित है। बाबा साहेब के द्वारा प्रशस्त मार्ग का अनुसरण करते हुए मोदी जी ने देश की मुख्यधारा में पीछे रह गये लोगों की उन्नति के संकल्प के साथ ही आत्मनिर्भर विकसित भारत का संकल्प लिया है। प्रदेश महामंत्री एवं संविधान निर्माता, भारत रत्न डा. भीम राव रामजी आम्बेडकर सम्मान अभियान के प्रदेश संयोजक श्री राम प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह तथा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य समेत पार्टी के सभी पदाधिकारियों, प्रदेश सरकार के मंत्रियों, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख, आयोग–बोर्ड–निगम के अध्यक्ष व सदस्यों सहित सभी जनप्रतिनिधियों, भाजपा के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नागरिकों के साथ संविधान निर्माता को माल्यार्पण करके नमन किया। प्रदेश में सभी बूथों पर संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमाओं व चित्रों पर माल्यार्पण के साथ ही संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। भाजपा 13 अप्रैल से प्रारम्भ हुआ संविधान निर्माता, भारत रत्न डा. भीम राव रामजी आम्बेडकर सम्मान अभियान 25 अप्रैल तक चलाएगी और बाबा साहेब के विचारों को लेकर जन–जन तक पहुंचेगी।

खून और पानी साथ नहीं बह सकते !

22 अप्रैल 2025 को जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुआ बर्बर आतंकी हमला, जिसमें 26 जानें गईं और 20 लोग घायल हुए, पूरे देश को गम और गुस्से से भर गया है। यह हमला केवल एक हिंसक घटना नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी शांतिप्रियता और कश्मीर में लौटती समृद्धि पर कायराना प्रहार था। जिस निर्ममता से पीड़ितों का धर्म पूछकर, आयतें सुनाने को कहकर उनकी हत्या की गई, वह आतंकवाद के घिनौने, सांप्रदायिक चेहरे को उजागर करता है। पाकिस्तान स्थित लश्कर–ए–तैयबा की शाखा, द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है; यह पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे छद्म युद्ध का एक और सबूत है।

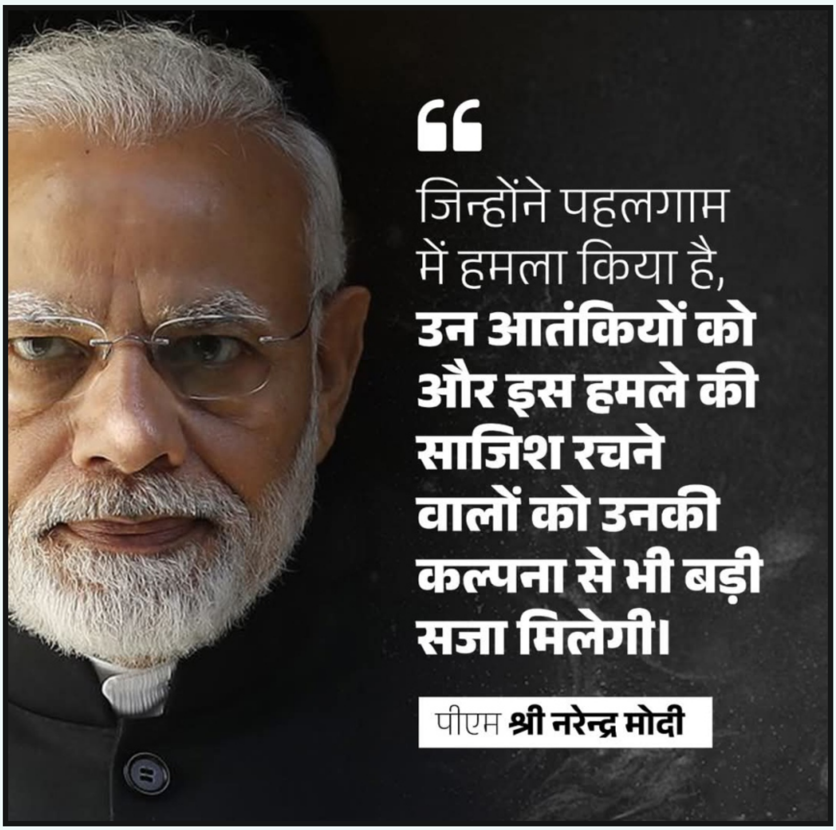

इस जघन्य कृत्य के बाद देश भर में उठी आक्रोश की लहर के बीच, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने केवल निंदा या कूटनीतिक विरोध तक सीमित न रहकर, त्वरित और अभूतपूर्व रूप से कठोर कदम उठाए हैं। यह कदम उस नए भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाते हैं जो आतंकवाद के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है, जो यह समझता है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जब एक पड़ोसी मुल्क लगातार आतंकवाद, बम, गोलियां और ड्रग्स भेज रहा हो, तो दूसरा पक्ष शांति की उम्मीद में चुप नहीं बैठ सकता या आतंकियों से बातचीत का राग अलाप नहीं सकता। पहलगाम हमले के जवाब में भारत की मोदी सरकार द्वारा लिए गए कठोर निर्णय पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हैं कि आतंकवाद को राष्ट्रीय नीति के रूप में इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी होगी। मोदी सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को त्याग नहीं देता। यह दर्शाता है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए दशकों पुरानी संधियों पर भी पुनर्विचार करने से नहीं हिचकेगा। सहयोग और आतंकवाद साथ–साथ नहीं चल सकते। इसके साथ

ही, अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। कूटनीतिक मोर्चे पर, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा पर रोक लगा दी गई है और पूर्व में जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को एक सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। ये सभी कदम आतंकवाद के प्रति भारत के कठोर एवं मजबूत रुख को रेखांकित करता है।

आज जब भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, तो यह याद करना आवश्यक है कि पहले की सरकारों का रवैया कैसा था। कांग्रेस/यूपीए शासनकाल में भारत ने इतिहास के कुछ सबसे भयानक आतंकी हमले झेले, लेकिन प्रतिक्रिया अक्सर ढुलमुल, अप्रभावी और केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित रही। क्या हम 26/11 मुंबई हमला भूल सकते हैं? 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्री रास्ते से आए और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को रक्तरंजित कर दिया। 166 निर्दोष लोग मारे गए, घंटों तक ताज और ओबेरॉय जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर आतंकवादियों का कब्जा रहा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की प्रतिक्रिया? जांच, डोजियर सौंपना, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करना। सुरक्षा तंत्र की विफलताएं और समन्वय की कमी स्पष्ट थी। क्या पाकिस्तान पर कोई सीधा, दंडात्मक प्रहार हुआ? नहीं। क्या हम मुंबई ट्रेन धमाके भूल सकते हैं, जिसमें 200 से अधिक जानें गईं और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए? या जयपुर धमाके, जिसने पिंक सिटी को 63 निर्दोषों के खून से लाल कर दिया? हर बार वही कहानी दोहराई गई जांच, निंदा, मुआवजे की घोषणाएं, लेकिन आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करने का संकल्प नदारद था। भारत एक 'सॉफ्ट स्टेट' की छवि बना चुका था, जो केवल घाव सहना जानता था, डोजियर लिखता रहा और निर्दोष मरते रहे।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। जब उरी में हमारे 19 सैनिक शहीद हुए, तो भारत ने केवल 10 दिनों के भीतर नियंत्रण रेखा (स्व्ब) पार कर आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए सर्जिकल स्ट्राइक। यह एक साहसिक और अभूतपूर्व कदम था जिसने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। जब पुलवामा में 40 जवानों की शहादत हुई, तो भारत ने 12 दिनों के भीतर पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर हवाई हमला किया। यह हमला भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रमाण था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं

कहा कि यह "नया भारत" है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारेगा। यही फर्क है निर्णायक नेतृत्व और पिछली सरकारों की नीतिगत पंगुता में।

लेकिन क्या हम ऐसी दृढ़ता की उम्मीद उन लोगों से कर सकते हैं जिनका आतंकवाद पर अपना इतिहास ही संदिग्ध है? क्या हम बटला हाउस एनकाउंटर के बाद की उन शर्मनाक खबरों को भूल सकते हैं, जिनमें दावा किया गया कि मारे गए आतंकवादियों की तस्वीरें देखकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे? आतंकवादियों के लिए आंसू ? यह किस मानसिकता का परिचायक है? जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, जो हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराते हैं, वे आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार कैसे कर सकते हैं? वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का उनका इतिहास रहा है। उनका रवैया तुष्टिकरण का रहा है, कार्रवाई का नहीं।

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भी कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया, सैफुद्दीन सोज़ और तारिक हमीद कर्रा पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं। वे इस तरह पाकिस्तानी मीडिया और ٰ٠ٰ की भाषा बोल रहे हैं, मानो इस्लामाबाद का प्रचार दोहरा रहे हों। ऐसा लगता है कि ये नेता पाकिस्तान की नज़र में 'आँखों के तारे' बनने की कोशिश में लगे हैं, मानो दुश्मन की खुशामद करना इनके लिए राष्ट्रहित से ऊपर हो गया है। उनका यह रवैया पहलगाम में शहीद हुए बेगुनाह लोगों की याद का तथा सीमा पर डटे वीर जवानों के बलिदान का अपमान है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है, तब तक किसी भी कूटनीतिक वार्ता का विचार सिरे से ख़ारिज होना चाहिए – टेरर और टॉक साथ-साथ नहीं चल सकते।" सिंधु जल संधि जैसे समझौते भी बेमानी हैं जब पड़ोसी मुल्क सीमा पार से गोलियाँ, बम और नशीले पदार्थ भेजकर हमारे देश को लहूलुहान करने पर तुला हो। देशवासियों की मांग है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान का पक्ष लेना बंद करें और याद रखें कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है।

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का संदेश स्पष्ट और अटल है: आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। पहलगाम के बाद उठाए गए सभी कठोर कदम इसी अटूट संकल्प का प्रमाण हैं। भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा की कीमत पर नहीं। जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद का निर्यात बंद नहीं करता, उसे भारत के इसी कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। यह नया भारत है, जो अपनी रक्षा करना जानता है। (लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

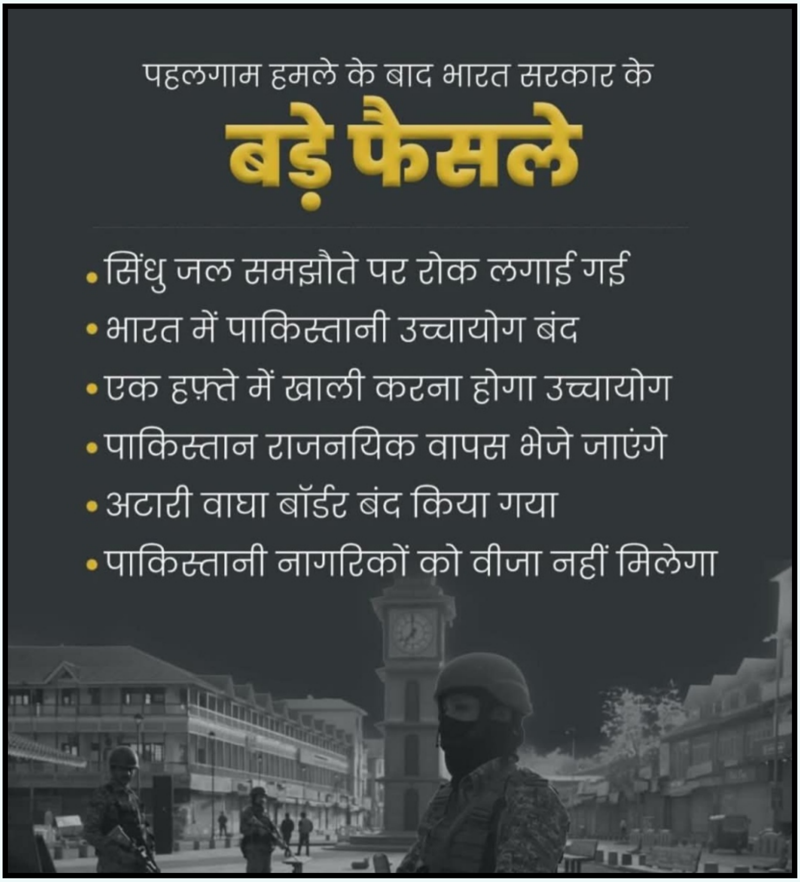

भाजपा का सबके सम्मान का संकल्प : धर्मपाल

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने रविवार को अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रम में संवाद करते हुए कहा कि मोदी सरकार व योगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के सबके विकास का संकल्प है। यही कारण है कि भाजपा सरकार की योजनाएं अनुसूचित वर्ग के सामाजिक व आर्थिक उत्थान का आधार बनीं है। कोई भी कार्यकर्ता घर पर खाली ना बैठे, सभी कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक कार्यक्रमों, अभियानों में जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए काम करना है। बहराइच के भाजपा जिला कार्यालय में अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रम में अनुसूचित मोर्चा के जिला एवं मंडल पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने संगठनात्मक मजबूती पर बल दिया। उन्होंने जिले के मंडल अध्यक्षो, निवर्तमान मंडल अध्यक्षो तथा पूर्व मंडल अध्यक्षो के साथ भी बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की। साथ ही उन विधानसभाओं के मंडल अध्यक्षो और शक्तिकेन्द्र संयोजक की बैठक भी ली जहां पिछले चुनाव में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद किया।

श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब डा. भीमराव आम्बेडकर से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा भाजपा की बाबा साहेब के सम्मान के साथ ही उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता है। भाजपा सरकार तथा संगठन में अनुसूचित जाति वर्ग के साथ सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व और सबके सम्मान का संकल्प समाहित है। यह सिर्फ रैलियों, भाशणों तथा बैठको में व्यक्त करने का विशय नहीं है। बल्कि यह भाजपा के संगठनात्मक ढांचे तथा भाजपा सरकारों की संरचना में परिलक्षित होता है।

भाजपा ही एक मात्र राजनैतिक दल है जिसमें प्रत्येक जाति व वर्ग के कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता के अनुसार संगठन व सरकार में उच्चतम पदो तक पहुंचने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने बाबा साहेब डा. भीमराव आम्बेडकर जी का विरोध और अपमान किया। अनुसूचित वर्ग को वोट बैंक की तरह उपयोग किया। इन दलो के शासनकाल में अनुसूचित जाति वर्ग गरीबी, अपमान व शोशण का शिकार रहा। सपा की सरकार के समय अनुसूचित जातिवर्ग ने घोर अपमान, हिंसा, जमींन और मकानों पर कब्जे और प्रताड़ना को झेला है। बेटियों का स्कूल जाना दूभर हो गया था। शौहदे बहन बेटियों को सरेराह बेइज्जत किया करते थे। लेकिन सपा की सरकार और तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से शौहदों, गुडों, अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण मिलता था। कांग्रेस की सरकारों के समय अनुसूचित वर्ग को छला गया और सपा की सरकार में अनुसूचित वर्ग को प्रताड़ित और अपमानित किया गया।

भाजपा सरकारों में मजबूत कानून व्यवस्था से हर बहन, बेटी सुरक्षित है। घर, मकान, खेत, खलिहान सुरक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित है। भाजपा सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं ने अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण को गति दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अनुसूचित जाति वर्ग के साथ ही सभी वर्गों की आर्थिक उन्नति का संकल्प निहित है। भाजपा की केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार ने बाबा साहेब डा. भीमराव आम्बेडकर के संविधान की मजबूती और अनुसूचित वर्ग के आरक्षण सहित तमाम अधिकारों को पूरी मजबूती के साथ सुरक्षित करने का काम किया।

श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस सहित सपा, बसपा व अन्य राजनैतिक दल किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा संचालित है। इसलिए इन दलों में परिवारवादी, जातिवादी तथा सामान्तवादी मजबूत सोच है। जबकि भाजपा एक परिवार की तरह काम करने वाला राजनैतिक दल है जिसमें किसी भी जाति या वर्ग का, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी में किसी भी पद तक पहुंचकर पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। भाजपा की राश्ट्रवादी नीतियों से राश्ट्र मजबूत व सुरक्षित है भाजपा सरकार में ही सबकी आर्थिक, सामाजिक मजबूती तथा राजनैतिक भागीदारी के साथ सम्मान सुरक्षित है। हमें लोगों के बीच में जाना है। विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करना है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास के मंत्र के साथ सबको साथ जोड़ना है।

समाजवादियों द्वारा बाबा साहब का अपमान

समाजवादी पार्टी के पोस्टर एवं होर्डिंग में बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी चित्र से आधा चेहरा हटाकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का चेहरा जोड़ने से आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर के अपमान के विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में अटल चौक, हजरतगंज स्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला, राज्यसभा सांसद बृजलाल, सदस्य विधान परिशद लाल जी निर्मल, मुकेश शर्मा, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी व जिला अध्यक्ष विजय मौर्या सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओ ने अनुसूचित मोर्चा के नेतृत्व में बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा किए गए बाबा साहब के अपमान के विरोध में प्रदर्शन किया।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने शिक्षा, समानता और संवैधानिक मूल्यों के लिए जीवनभर संघर्श किया। लेकिन अपने पूरे जीवन में सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव बाबा साहब के बराबर खड़े होने का दुस्साहस कर रहे है। उन्होंने कहा सपा की होर्डिंगों और पोस्टरों में बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की आधी तस्वीर काटकर उसमें अखिलेश यादव का चित्र जोड़ना बाबा साहब का अपमान है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि क्या समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यह नही पता कि संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर न किसी जाति के थे, ना किसी पार्टी के? वे विचारधारा थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उनके समक्ष प्रस्तुत करना सीधे तौर पर दलितों, वंचितों के संघर्श का अपमान है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का पूरा जीवन समाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई में बीता जबकि अखिलेश यादव की पूरी राजनीति अपने पिता द्वारा दी गई कुर्सी बचाने में लगी रही। परिवारवाद का सबसे बड़े उदाहरण समाजवादी पार्टी ने क्या कभी किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाया? क्या किसी को समाजवादी पार्टी ने संगठन का शीर्ष नेतृत्व सौंपा?

श्री चौधरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर के नाम से बने संस्थानों से डॉ. आम्बेडकर का नाम हटा दिया था। ये वही अखिलेश यादव है जिनके मंत्री आजम खां ने बाबा साहब को सार्वजनिक रूप से भू–माफिया बताया और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कुछ नही किया।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर को डॉ. आम्बेडकर के बराबर लगाना न सिर्फ अहंकार है बल्कि दलित समाज की भावनाओं के साथ किया गया एक निंदनीय खिलवाड़ है। बाबा साहब के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नही किया जाएगा।

राज्यमंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास दलितों के विश्वासघात से भरा है। अब बाबा साहब की छवि से दलितों को छलने की कोशिश हो रही है। यह राजनीतिक धोखाधड़ी है। सपा की राजनीति मुस्लिम तुश्टीकरण, जातिय ध्रुवीकरण पर आधारित रही है, ये जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का अपमान करने वालों को जनता कभी भी माफ नही करेगी। अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचन्द्र कन्नौजिया ने कहा कि दलितों की राजनीति करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब सिर्फ प्रतीकों की शरण में है क्योंकि उनके पास न नीति है, न नीयत। पोस्टर और भाशणों से ना तो दलितों का भला होता है और ना ही इतिहास बदला जा सकता है।

राज्यसभा सांसद श्री बृजलाल ने कहा कि दलित समाज जानता है कि अखिलेश यादव को सिर्फ दो चीजों की चिंता है। मुस्लिम वोट बैंक और अपने परिवार की विरासत। यही वजह है कि वे कभी भी किसी दलित को अपनी सत्ता और संगठन में शीर्ष पद नही देते। विधान परिषद सदस्य श्री लालजी निर्मल ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बाबा साहब का अपमान करने वाले इस शर्मनाक प्रयास के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

सांसद खेल महाकुम्भ
कबड्डी
बास्केटबॉल

रोजगार मेला
के तहत
प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी
द्वारा
देश भर में 47 स्थानों पर सरकारी नौकरियों में चयनित 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण

अनुसूचित जाति संवाद
धर्मपाल जी
श्री शिव सागर गौतम जी

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91, शीर्षक कोडः UPHIN16701, डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2024-26
अप्रैल द्वितीय अंक 2025 –प्रेषित डाकघर –R.M.S. चारबाग, लखनऊ –प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।